

डॉ. अंबेडकर का 69वाँ महापरनिर्वाण दिवस

प्रलम्ब के लिये:

[डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर](#), [भारतीय संविधान](#), [भगवान बौद्ध](#), [सामाजिक समानता](#), [सकारात्मक कार्रवाई](#), [पूना समझौता](#), [भारतीय वित्त आयोग](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम, 1934](#), [दामोदर घाटी परियोजना](#), [हिराकुंड बाँध](#), [रोज़गार कार्यालय](#), [प्रारूप समिति](#), [वधिका समक्ष समानता](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [नीतिनिदेशक सदिशांत](#) ।

मेन्स के लिये:

[कल्याणकारी राज्य](#), [जाति-आधारित भेदभाव](#), सामाजिक न्याय में डॉ. अंबेडकर का योगदान, संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण के प्रयास ।

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [भारतीय संविधान](#) के मुख्य वास्तुकार और सामाजिक न्याय के अग्रदूत भारत रत्न [डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर](#) की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को 69वाँ महापरनिर्वाण दिवस मनाया गया ।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरनिर्वाण दिवस सामाजिक सुधार, न्याय और समानता पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए उनकी वरिष्ठता का सम्मान करता है ।
- "महापरनिर्वाण" शब्द [बौद्ध](#) दर्शन से निकला है जो [जन्म और मृत्यु के चक्र](#) से मुक्ति का प्रतीक है तथा बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन है ।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर

(14 अप्रैल, 1891-06 दिसंबर, 1956)

बाबासाहेब अंबेडकर

भारतीय संविधान के जनक



संक्षिप्त परिचय

- एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक और तुलनात्मक धर्मों के विचारक
- वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942) में श्रम मामलों के जानकार सदस्य
- नए संविधान के लिये मसौदा समिति के अध्यक्ष
- भारत के प्रथम विधि मंत्री
- मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित (1990)

योगदान

- हिंदुओं के खिलाफ वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व
- तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया
- दलित वर्गों के लिये पृथक् निर्वाचक मंडल के विचार को त्यागने के लिये महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये
- प्रांतीय विधायिकाओं में वंचित वर्गों के लिये आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में 18% कर दिया गया था।
- जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध (अनुच्छेद 370)
- समान नागरिक संहिता का समर्थन
- अनुच्छेद 32 को “संविधान की आत्मा और इसके हृदय” के रूप में संदर्भित किया

त्याग-पत्र और बौद्ध धर्म

- हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण वर्ष 1951 में उन्हें कैबिनेट से त्याग-पत्र देना पड़ा
- बौद्ध धर्म को अपनाया; उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएँ

- मूकनायक (1920)
- बहिष्कृत भारत (1927)
- समता (1929)
- जनता (1930)

संगठन

- ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ की स्थापना (1923)
- स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना (1936)
- शेड्यूलड कास्ट फेडरेशन की स्थापना (1942)

पुस्तकें

- जाति का विनाश (Annihilation of Caste)
- बुद्ध या कार्ल मार्क्स (Buddha or Karl Marx)
- अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बने (The Untouchable: Who are They and Why They Have Become Untouchables)
- हिंदू महिलाओं का उदय और पतन (The Rise and Fall of Hindu Women)

डॉ. अंबेडकर ने किस प्रकार सामाजिक न्याय का समर्थन किया?

- **शोषितों के समर्थक:** डॉ. अंबेडकर दलितों, महिलाओं और मज़दूरों के लिये आशा की करिण बनकर उभरे। उन्होंने [जाति आधारित भेदभाव](#) को मटाने और [सामाजिक समानता](#) सुनिश्चित करने के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया।
 - उनका समर्थन प्रणालीगत बाधाओं को समाप्त करने और हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने तक फैला हुआ था।
- **सशक्तीकरण पहल:** डॉ. अंबेडकर ने हाशिये पर पड़े समूहों के उत्थान के लिये [सकारात्मक कार्रवाई](#) का समर्थन किया, ताकि हाशिये पर पड़े समूहों द्वारा सामना किये गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिये [शिक्षा, रोज़गार और राजनीति में आरक्षण](#) जैसी नीतियों का प्रावधान किया जा सके।
 - [अनुच्छेद 15\(4\), 16\(4\) और 334](#) के तहत आरक्षण शिक्षा, सार्वजनिक रोज़गार, वधायी नकियों और चुनावों में हाशिये के समूहों के लिये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
 - शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और बहिष्कृत समुदायों को सशक्त बनाने के लिये [बहिष्कृत हितकारिणी सभा \(1923\)](#) की स्थापना की।
- **दलितों की आवाज़:** दलितों को मंच प्रदान करने और सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने के लिये [मूकनायक \(मूक नेता\)](#) समाचार पत्र की स्थापना की।
- **अग्रणी आंदोलन:** सार्वजनिक जल संसाधनों तक समान पहुँच का समर्थन करते हुए [महाड सत्याग्रह \(1927\)](#) सहित ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया।
 - वर्ष 1930 में [कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन \(नासिक सत्याग्रह\)](#) का नेतृत्व किया, ताकि पूजा स्थलों पर जाति आधारित प्रतिबंधों को तोड़ा जा सके, जो अस्पृश्यता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई का प्रतीक है।
- **पूना समझौता (1932):** [पूना समझौता](#) पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दलितों के लिये पृथक नरिवाचिका मंडलों के स्थान पर आरक्षण सिटें स्थापित कीं, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ।

संवधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर का क्या योगदान था?

- **प्रारूप समिति के अध्यक्ष:** वर्ष 1947 में नियुक्त [प्रारूप समिति](#) के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अंबेडकर ने विश्व के सबसे बड़े लिखित संवधान को तैयार करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का निरीक्षण किया।
 - विविध विचारों और चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वर्ष 1949 में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधानों के साथ संवधान को अपनाया जाए।
- **मौलिक अधिकार:** डॉ. अंबेडकर ने संवधान के भाग III का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो [व्यक्ति के समक्ष समानता](#), भेदभाव के खिलाफ संरक्षण ([अनुच्छेद 15, 17](#)) और अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
 - शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण के प्रावधान ([अनुच्छेद 15\(4\), 16\(4\)](#)) का उद्देश्य हाशिये पर पड़े समुदायों का उत्थान करना और समानता सुनिश्चित करना है, जो सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की रीढ़ है।
- **अनुच्छेद 32: "संवधान की आत्मा"** कहे जाने वाले [अनुच्छेद 32](#) में नागरिकों को [मौलिक अधिकारों](#) के प्रवर्तन के लिये [सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय](#) में जाने का अधिकार दिया गया है।
 - उन्होंने संवधानिक गारंटियों की रक्षा में इसकी केंद्रीय भूमिका पर बल दिया।
- **संसदीय लोकतंत्र:** उन्होंने सरकार के संसदीय स्वरूप की वकालत की, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।
 - इस प्रणाली को समतावादी सिद्धांतों को बनाए रखने और राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- **संघीय संरचना:** इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को संतुलित करते हुए [दोहरी राजनीति](#) की संकल्पना की गई।
 - यह ढाँचा भारत की अद्वितीय सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल बनाया गया था, जिससे [एकता और लचीलापन](#) दोनों सुनिश्चित हो सके।
- **राज्य नीति के नदिशक सिद्धांत:** [नदिशक सिद्धांतों](#) को [कल्याणकारी राज्य](#) बनाने, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता और बेहतर जीवन स्तर जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया।
 - यद्यपि ये सिद्धांत न्यायोचिंत नहीं हैं, फिर भी ये भारत में नीति-निर्माण का अभिन्न अंग बने हुए हैं।

राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर का क्या योगदान था?

- **आर्थिक ढाँचा:** डॉ. अंबेडकर के शैक्षणिक योगदान ने कई आर्थिक संस्थाओं की नींव रखी।
 - उनकी डॉक्टरेट थीसिस ने [भारत के वित्त आयोग](#) के निर्माण और [भारतीय रिज़र्व बैंक \(RBI\) अधिनियम, 1934](#) के नीति ढाँचे को प्रभावित किया।
- **अवसंरचना विजय:** [दामोदर घाटी परियोजना](#), [हीराकुंड बाँध](#) और [सोन नदी परियोजना](#) जैसी बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं की परिकल्पना की गई और उन्हें बढ़ावा दिया गया, ताकि स्थायी संसाधन प्रबंधन और राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित हो सके।
 - [राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली](#) की संकल्पना की, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया।
- **रोज़गार सुधार:** देश भर में व्यवस्थित रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये नौकरी नियुक्ति प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने हेतु [रोज़गार कार्यालयों](#) की स्थापना की गई।
- **सामाजिक और आर्थिक न्याय:** समावेशी नीतियों के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने की वकालत की और हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिये शासन संरचनाओं में सामाजिक न्याय को एकीकृत करने का समर्थन किया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सरकार की श्रद्धांजलि

- **भारत रत्न पुरस्कार:** डॉ. अंबेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, [भारत रत्न](#) से सम्मानित किया।

